

हर रात के बाद सवेरा आता है, खुशिया जरूर आयेगी धैर्य रखिए।
- अज्ञात



कठिनाइयों का पहाड़

ये काम प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक राहत तो दे सकते हैं, लेकिन उनके कौशल के साथ न्याय नहीं कर सकते। इन कुशल कामगारों का जो काम छूटा है, उससे उस काम की कोई तुलना नहीं हो सकती जो उन्हें उपलब्ध कराया गया है।

आरती शर्मा।

महामारी और लॉकडाउन ने हमारे सामने कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा कर दिया है लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों मोर्चों पर हमारी लड़ाई अच्छे नतीजे लेकर आ रही है। खासकर लॉकडाउन के साइड इफेक्ट से तात्कालिक तौर पर उबरने के ठोस संकेत मिलने लगे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में बेरोजगारी का स्तर अभी लॉकडाउन से ठीक पहले वाली स्थिति में पहुंच गया है। 21 जून को समाप्त हुए सप्ताह में यह 8.5 फीसदी पाया गया, जो मार्च में लॉकडाउन घोषित होने से पहले की 8.75 फीसदी बेरोजगारी से थोड़ा नीचे ही है।

ध्यान रहे, लॉकडाउन घोषित होने के बाद जब दफ्तरो और कारखानों में

कामकाज बंद हुआ और तमाम कंपनियों ने बिना कुछ कहे-सुने अपने शटर गिरा दिए, तो उनमें काम करने वाले मजदूर और कारीगर न केवल बेरोजगार हो गए बल्कि अचानक वे हर तरह की असुरक्षा से घिर गए। महामारी की दहशत, पैसों की तंगी और काम-धंधे की अनिश्चितता ने उन्हें सब छोड़-छाड़कर अपने गांवों की ओर कूच करने को मजबूर कर दिया। इसी का एक परिणाम यह हुआ कि मार्च के 8.7 फीसदी से बढ़ते-बढ़ते देश में बेरोजगारी का स्तर 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में 27.1 फीसदी तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद हालात सुधरने शुरू हुए। खास तौर पर जून के इन तीन हफ्तों में बेरोजगारी गिरती हुई 17.5 फीसदी और 11.6 फीसदी के बाद 8.5 फीसदी पर आ गई।

सीएमआईई की यह रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि स्थिति में यह सुधार गांव लौटे प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में या उसके आसपास ही काम उपलब्ध कराने के प्रयासों का नतीजा है। ये प्रयास ज्यादातर मनरेगा के ही तहत हुए हैं, जिसका एक मतलब यह भी है कि बेरोजगारी प्रतिशत में कमी के इन आंकड़ों को एक हद से ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती। ये काम प्रवासी मजदूरों को तात्कालिक राहत तो दे सकते हैं, लेकिन उनके कौशल के साथ न्याय नहीं कर सकते। इन कुशल कामगारों का जो काम छूटा है, उससे उस काम की कोई तुलना नहीं हो सकती जो उन्हें उपलब्ध कराया गया है। इस तरह की मदद को रोजगार मानकर हम तात्कालिक तौर पर अपने आंकड़े भले दुरुस्त कर लें, लेकिन

इन्हें वास्तविक रोजगार के रूप में देखना भविष्य के रिसर्चों की राह कठिन बनाएगा।

इकॉनमी के नजरिए से देखें तो खुश होने वाली खबर यह है कि लॉकडाउन के कारण अचानक बंद हो गई कंपनियों में जैसे-जैसे काम शुरू हो रहा है, वे गांव जा चुके अपने कर्मचारियों की भी सुध ले रही हैं। उनसे संपर्क स्थापित कर रही हैं, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दे रही हैं और उनकी वापसी के लिए परिवहन की व्यवस्था भी कर रही हैं। गांव लौटे मजदूर भी बदले हालात में वापसी की इच्छा जता रहे हैं। इस प्रक्रिया में एंजॉय और एंजॉयी के बीच विश्वास बहाल हो जाए तो अर्थव्यवस्था को पट्टी पर लौटाने की दिशा में यह जरूर एक ठोस कदम होगा।

जैनधर्म

अशोक बोहरा। बुद्ध की मूर्तियां भी योग साधना में स्थापित हैं। बौद्ध और जैनधर्म में भी योग की महत्ता पर काफी कुछ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से संयुक्तराष्ट्र संघ ने भी योग के महत्व को स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी योग को लेकर स्वयं बेहद जागरूक हैं। वह योग करते हुए अपने कई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं। फिट इंडिया, हिट इंडिया उनका मूलमंत्र है। इसके साथ वह लोगों से अपील करते हैं कि आप योग के जरिए अपने मन, मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखें, जिससे आपका सहयोग देश के विकास में अच्छे तरीके से हो। विज्ञान और विकास के बढ़ते कदम तनाव की जिंदगी दे रहा है। जिंदगी की गति अधिक तेज हो चली है। लोगों के जीने का नजरिया बदल रहा है। काम का अधिक दबाव बढ़ रहा है इससे हाईपर टेंशन, और दूसरी बीमारियां फैल रही हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

लूट की दुकान

भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आई सी आई सी आई बैंक, आई डी बी आई बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स, इंडस इंड बैंक, यस बैंक और ए बी एन एमरो बैंक। यह कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां देश की आम जनता अपने खून पसीने की कमाई को जमा करती है। लोगों को यह विश्वास है कि उनका पैसा इन बैंकों या संस्थाओं के पास सुरक्षित रहेगा और जरूरत पड़ने पर यह पैसा जनता को वापस भी मिल सकेगा। पहले से ही बैंकिंग संस्थाओं की आर्थिक हालत काफी नाजुक चल रही है और उस नाजुक हालात के बीच अगर राजनीतिक दबाव में इन बैंकों को जबरन दान देने के लिए मजबूर किया जाए तो जो पैसा दान में जाएगा वह जनता का ही होगा क्योंकि बैंकों के पास अपना कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार जिस समय केंद्र की सत्ता में थी तो उस समय इन बैंकों और संस्थाओं ने राजीव गाँधी फाउंडेशन को दान दिया था। राजीव गाँधी फाउंडेशन गाँधी परिवार का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है और किसी भी ऐसी संस्था या बैंक जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ हो, उसे इस तरह का दान इस तरह के प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं करना चाहिए लेकिन क्योंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और सरकार का नियंत्रण हमेशा से ही गाँधी परिवार के पास था। इस तरह की अवांछित गतिविधियां धड़ल्ले से अंजाम दीं गयीं। कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री और सोनिया गाँधी सुपर पी एम के रोल में थीं, उन दस सालों में राजीव गाँधी फाउंडेशन ने प्राइवेट सेक्टर की भी सैंकड़ों कंपनियों से चंदा लिया है। देश की जनता खुद यह फैसला करे कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिनमे से बहुत सारी कंपनियों में जनता का पैसा लगा हुआ है और वे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हैं, वे इस ट्रस्ट को दान देने पर मजबूर क्यों थीं।

इस गुस्से की अभिव्यक्ति में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग भी शामिल हो चुकी है। हालांकि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में इस विचार को व्यावहारिक मानने वालों की भी कमी नहीं है।

बापू भी थे खिलाफ

उमेश चतुर्वेदी।

लद्दाख में लाइन ऑफ एक्जुअल कंट्रोल पर चीनी करतूतों को रोकने के क्रम में भारत के बीस रणबाँकुरों के बलिदान के बाद देश में चीन के खिलाफ गुस्सा उठना स्वाभाविक है। इस गुस्से की अभिव्यक्ति में चीनी सामान के बहिष्कार (बॉयकॉट) की मांग भी शामिल हो चुकी है। हालांकि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में इस विचार को व्यावहारिक मानने वालों की भी कमी नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2018-19 में चीन और भारत के बीच करीब 6.09 लाख करोड़ का कारोबार हुआ, जिसमें चीन का पलड़ा भारी रहा। चीन ने भारत को 4.92 लाख करोड़ का निर्यात किया, जबकि भारत से उसने सिर्फ 1.17 लाख करोड़ का आयात किया। ऐसे में यह सवाल बनता है कि भारत का उद्योग और आम समाज जिस तरह से चीनी सामानों और वहां से आए कच्चे माल पर आश्रित हो चुका है, उसे देखते हुए क्या वह इनके आयात में कटौती का जोखिम उठा सकेगा?

ऐसे ही सवाल गांधी जी के सामने भी उठे थे जब 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर एक तरह से स्वदेशी अभियान का श्रीगणेश किया था। हालांकि स्वदेशी के पक्ष में विदेशी के



बहिष्कार को लेकर गांधी का आंदोलन मौलिक नहीं था। स्वदेशी की भावना इसके सोलह साल पहले ही जोर पकड़ चुकी थी, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था। उसके खिलाफ बंगाल में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ जो देखते-देखते पूरे भारत का आंदोलन बन गया। इसी आंदोलन के दौरान 7 अक्टूबर 1905 को पुणे में विदेशी वस्त्रों की पहली होली जलाई गई थी। उन दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था।

'इंडियन ओपिनियन' में उन्होंने इसके खिलाफ लिखा था। लेकिन भारत लौटने और देश भ्रमण करने के बाद गांधी को लगा कि देश का स्वामिना

तमी जागृत हो सकता है, जब स्वदेशीकरण पर जोर दिया जाए।

इसके पहले हिंद स्वराज में वे स्वदेशी का गुणगान कर ही चुके थे, हालांकि, स्वदेशी के जरिए ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने की बातें सार्वजनिक तौर पर उससे काफी पहले से शुरू हो गई थीं। जुलाई 1903 की सरस्वती में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लिखी कविता प्रकाशित हुई थी। जिसकी कुछ पंक्तियां हैं, 'अरे भाई! अरे प्यारे! सुनो बात स्वदेशी वस्त्र से शोभित करो गातध वृथा क्यों फूकते हो देश का दामध करो मत और अपना नाम बदनाम!' बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी के स्वदेशी अभियान का भी उस दौर में कई लोगों ने समर्थन नहीं किया था। गांधी भक्त के रूप में विख्यात दीनबंधु एंड्रयूज ने भी इसका विरोध किया था।

1921 में ही गांधी जी को लिखे एक पत्र में एंड्रयूज ने लिखा था, 'मैं जानता हूँ कि गरीबों की सहायता की भावना से ही आप विदेशी कपड़ों की होली जला रहे हैं लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आप गलती पर हैं। विदेशी शब्द में जातीयता की भावना को उभारने वाली बात छिपी हुई है। उन सुंदर और कोमल वस्त्रों के ढेर को आग लगाते हुए आपका चित्र देखकर मेरे मन को गहरा धक्का लगा है। मुझे भय है कि कहीं यह कदम, स्वार्थपरायण राष्ट्रवाद की ओर न ले जाए।'

सूडोकू नवताल- 5368					सूडोकू नवताल- 5367 का हल									
5	9	8	3	2	8	2	5	3	6	7	9	1	4	
2		4				4	6	1	8	9	2	3	7	5
3	8		5	2	6	1								
	7									9	5			
9		3	6		8	7					4			
2	6										1			
		5	2	7	1					8	6			
6					4						7			
		8	9	6						4		2		

अपना ब्लॉग नए आनंद की अनुभूति होगी

मोहन। आपके पास काफी अतिरिक्त समय रहता है। जरा यह अलग-सा प्रयोग करके देखें। जिस काम में आप जितना समय लगाते हैं, उसका दूना समय लगाकर देखिए। चाहे नहाना हो, गाना हो या आना-जाना हो। आपको नए आनंद की अनुभूति होगी। घरेलू गिरफ्तारी के इन दिनों में टीवी सबका बड़ा साथी है लेकिन टीवी चैनलों पर जिस तरह से कोरोना के हताहतों और चीनी हमले की खबरें पेश की जा रही हैं, उनसे करोड़ों लोग हताश, निराश और उदास होने लगते हैं। टीवी देखे बिना तो रहा नहीं जा सकता लेकिन संभलकर देखें, कम देखें और उस पर कुछ फिल्में, नाटक, काव्य आदि का आनंद लें तो बेहतर रहे। सबसे अच्छा यह होगा कि दोपहर से शाम तक के कुछ घंटे स्वाध्याय में लगाए जाएं। मैं जब भी जेल जाता था तो प्रेमचंद और शरतचंद्र चटर्जी आदि के उपन्यास, भारतीय और पश्चिमी दार्शनिकों के ग्रंथ और इतिहास व राजनीति की ताजा किताबें एक बड़े सूटकेस में पहले से भरकर रखता था।

